देश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

5393. **श्री राघवजी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक देश में राज्यवार ऐसे कितने टेलीफोन आवेदक थे, जिन्हें टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं

(ख) वर्ष 1993-94 में कितने लोगों ने टेलीफोन के लिए आवेदन किया है और इस वर्ष कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ग) 31 मार्च, 1994 तक लंबित पड़े मामलों में कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुखराम : (क) टेलीफोन अभ्यर्थियों की राज्यवार प्रतीक्षा सूची विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना समेकित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आठवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन की प्रतीक्षा अवधि को कम करके 2 वर्ष से नीचे लाना है और आठवीं योजना अवधि (1992—97) के अंत तक ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर तुरंत टेलीफोन प्रदान करना है। तदनुसार, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए 75 लाख नए कनेक्शनों की योजना बनाई गई है। 1992-93 और 1993-94 के दौरान 22.26 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

विवरण

31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में ऐसे आवेदकों की संख्या का ब्यौरा जिन्हें टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये थे।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	31-3-94 तक की प्रतीक्षासूची
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	155426
2.	असम	9820
3.	बिहार	35544
4.	गुजरात (दादर, दिव, दमन और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित)	198808
5.	हरियाणा	67335
6.	हिमाचल प्रदेश	18415
7.	जम्मू एवं कश्मीर	18190
8.	कर्नाटक	165886
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित)	314442
10.	मध्य प्रदेश	52587
11.	महाराष्ट्र (गोवा राज्य सहित)	341529
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	5217
13.	उड़ीसा	4171
14.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित)	189462
15.	राजस्थान	162571
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित)	310992
17.	उत्तर प्रदेश	125496
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम राज्य, अंडमान, निकोबार द्वीप समूह सहित)	68083
19.	दिल्ली	250901

Private Sector Trunk Phone Services

5394. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have decided to permit private companies to operate trunk phone services; and

(b) what are the details of this scheme and by when it is likely to be introduced ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) No Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

उत्तर प्रदेश में गांवों में डाकघर सुविधाएं

5395. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के अंत तक उत्तर प्रदेश में कितने गांवों में डाकघर नहीं थे;

(ख) उत्तर प्रदेश में जिलावार तथा श्रेणीवार कितने गांवों में डाकघर की सुविधा है;

(ग) जिलावार कितने गांवों में डाकघर की सुविधा नहीं है; और

(घ) भविष्य में जिलावार तथा श्रेणीवार कितने डाकघर खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुखराम : (क) वर्ष 1992-93 के अंत तक 1,01,148 गांव ऐसे थे, जिनमें डाकघर नहीं थे।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में 31-3-94 की स्थिति के अनुसार जिन गांवों में डाकघर हैं उनकी जिलावार तथा डाकघरों की श्रेणीवार संख्या और उन गांवों की जिलावार संख्या, जहां डाकघर नहीं है, अनुपत्र में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 170 अनुपत्र संख्या 110]

(घ) चालू वार्षिक योजना 1994-95 के लिए लक्ष्यों के आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

5396. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितने इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है,

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी लाइनें बढ़ाए जाने की संभावना है,

(ग) मध्य प्रदेश में कितने गांवों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है और राज्य में सभी गांवों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है, और

(घ) क्या सरकार ने सभी पंचायत-मुख्यालयों में टेलीफोन-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुखराम : (क) सूचना को अद्यतन बनाया जा रहा है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) मध्य प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,10,000 लाइनों की क्षमता की वृद्धि किए जाने की योजना है।

(ग) मध्य प्रदेश में 57644 ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। चालू 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकेंगी।

(घ) जी हां। सभी ग्राम पंचायतों में 1994-95 तक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने का कार्यक्रम है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन-कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

5397. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 नवम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में एक्सचेंज वार टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक शहर में इन प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज व्यक्तियों को विशेष रूप से ओ० वाई० टी० श्रेणी के अंतर्गत कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) 1 नवम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में एक्सचेंजवार टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन के आबंटन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या संबंधी सूचना अनुबंध के कॉलम 3, 4 तथा 5 में दी गई है, और ओ वाई टी कनेक्शनों को निपटाने की संभावित तारीख अनुबंध के कॉलम 6 में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं० III]

Audit of Government Accounts

5398. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) annual rate of audit of Government accounts carried out during the last three years.

(b) break-up of amount of loss detected as a result of audit during the period.

(c) whether any fresh guidelines are being issued to minimise the loss to Government and if so, details thereof.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) The audit of different categories of vouchers is conducted centrally with reference to percentages prescribed by the Comptroller & Auditor General of India from time to time. In addition, local inspections are conducted according to annual programmes which are prepared in accordance with the directions issued by the Comptroller & Auditor General of India. The extent of such audit differs from one Department to another. Separate norms exist for Civil, Defence, P & T